

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल गवालियर केम्प सागर मोप०

--- अपील - १०५ - २१ ---

१- उदयभान बल्द श्यामला आदिवासी ४गौड़ी

२- गुड़ी बाई पुत्री श्यामला आदिवासी ४गौड़ी

दोनों निवासी ग्राम चौकी तहसील राष्ट्रगढ़ जिला सागर मोप०

— अपीलार्थी गण

// विळम्ब //

मोप०शासन

— प्रति अपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा ४४ श २५ मोप०श० राजस्व संहिता १९५९

अपीलार्थी गण अधिकार्य न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय सागर सभाग
सागर के द्वारा अपील प्र०३० ८४/अ-२१/ वर्ष २०१४-१५ में पारित आदेश
दिनांक १८-२-२०१६ से दुख्ति होकर निम्न आधारों पर यह अपील पुस्तुत
करते हैं।

// प्रकरण के तथ्य //

- १- यहाँकि अपीलार्थी गण ग्राम चौकी तहसील राष्ट्रगढ़ जिला सागर के
स्थाई निवासी है मौजा चौकी द०न० २९ तहसील राष्ट्रगढ़ जिला सागर में
स्थित भूमि जिसका संख्या नंबर २०२ रकवा ०.५८० है तथा द०न० २०९ ,
रकवा ०.४०० है अपीलार्थी गणों के नाम से राजस्व रिकार्ड में वर्ण है।
अपीलार्थी गणों को शासन द्वारा उक्त भूमि पट्टे पर दी गई थी किन्तु
कई वर्षों से कष्टा होने के कारण शासन द्वारा उन्हें भूमि स्वामी अधिकार भी
दे दिये गये थे।

- २- यहाँकि दूसरी का भूमि उबड़ गाबड़ पथरीली भूमि है। इसलिए
अपीलार्थी गणों ने दिनांक २७-४-२०१३ को उक्त जमीन को विक्रय करने बाबत

27-4-16
@ubey
29-3-16.

(S)

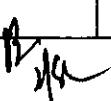
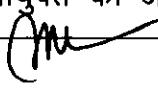
PK

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1101—दो / 16

जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
३-१-2016	<p>अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 84/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 18-2-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>2/ अपीलार्थी अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि ग्राम चौकी तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 202 रकवा 0.580 हेठो तथा खोकं 209 रकवा 0.400 हेठो अपीलाटों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलार्थियों को उक्त भूमि पट्टे में प्राप्त हुई थी। उक्त भूखण्ड उबड़ खाबड़ पथरीली भूमि है इसलिए अपलार्थीगण ने दिनांक 27-4-13 को विक्रय करने बावत आवेदन कलेक्टर सागर को प्रस्तुत किया। कलेक्टर सागर ने प्रकरण की विधिवत जांच न करते हुये मनमाने तरीके से दिनांक 9-12-14 को प्रकरण में आदेश पारित अपीलार्थी का आवेदन निरस्त कर दिया। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18-2-16 को यह निष्कर्ष निकालते हुये कि संहिता की 165 में संशोधन किया जा चुका है शासकीय पट्टे पर प्रदत्त भूमि को अंतरित करने की वांछा रखने तथा राजस्व अभिलेख में अहस्तांतरिणीय के रूप में अभिलिखित प्रविष्टि को हटाने की लिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें तथा अपील विधि अनुकूल न होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया किया कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील संहिता की धारा 165 के अधिनियम में संशोधन के पूर्व प्रस्तुत की गई थी और प्रकरण के पूर्व से प्रचलित होने से भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकते थे बल्कि पूर्व की भाँति ही कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त को अपना निर्णय पारित करना चाहिए</p>	 

था। अतः अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तकाँ के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष विक्रय अनुमति बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह लेख किया गया था प्रश्नाधीन भूमि पथरीली एवं उबड़-खाबड़ होने से अपीलार्थी भूमि का विक्रय कर बेटी के विवाह के लिए ली गई राशि वापिसी एवं जीवन यापन के लिए व्यवसाय करने के लिए विक्रय करना चाहता है। अपीलार्थी ने विक्रय अनुबंध पत्र की प्रति भी आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई थी, परन्तु कलेक्टर इन बिन्दुओं पर बिना विचार किये अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त अपने आदेश में म०प्र०० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में हुये नवीन संशोधन का उल्लेख करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अहस्तांतरणीय प्रविष्ट हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ अपील निरस्त की है। चूंकि अपीलार्थी की अपील उक्त संशोधन के पूर्व से प्रचलित थी इसलिए उक्त संशोधन का प्रभाव इस अपील प्रकरण पर नहीं पड़ता है। इसलिए अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहां तक विक्रय अनुमति दिये जाने के प्रश्न है अपीलार्थी की परिवारिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का दृष्टिगत रखते हुये एवं सदभाविक रुख अपनाते हुये अपीलार्थी को प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल परिकार हो।

सदस्य

B
M/S